

①

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(मानव अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल.

क्रमांक एफ 7-55/2014/1/माअप्र.
प्रति,

भोपाल, दि० 12, 01.2015

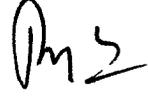
समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,
शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश शासन,

विषय- प्रदेश के समस्त सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में ।

उपरोक्त विषय के संबंध में आयोग के निर्देशों का कृपया अवलोकन करे। (प्रति संलग्न है) आयोग ने लेख किया है कि ऐसे कई प्रकरण आयोग के सामने आये हैं, जिनमें पेंशन व अन्य स्वत्व मिलने में अत्यधिक विलंब किया गया है। यदि सेवापुस्तिका की डुप्लीकेट पुस्तिका निर्माण आवश्यक है तो कृपया निर्माण संबंधी कार्यवाही एक निश्चित अवधि में पूर्ण कर ली जाये, ताकि सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी न हो। ऐसे जितने भी प्रकरण आपके विभाग में लंबित हैं, उनमें एक निश्चित अवधि में निराकरण कराने की व्यवस्था करें।

उक्त निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए समय-सीमा में विषयान्तर्गत पेंशन प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार



(बी.आर.विश्वकर्मा)

उप सचिव

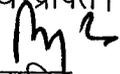
मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग(माअप्र)

भोपाल, दि० 12, 01.2015

क्रमांक एफ 7-55/2014/1/माअप्र.
प्रतिलिपि-

सचिव, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की ओर उनके पत्र क्र० 26132/माअआ/वि.शा./276/नीमच/12, दि० 09.12.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।



उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग(माअप्र)

ok

2

F7-55/2014

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग
पर्यावास भवन, खण्ड-1, प्रथम तल, अरेरा हिल्स भोपाल

1725
19/12/14

कमांक 26132 / माअआ / वि.शा. / 276 / नीमच / 12

भोपाल, दिनांक 09/12/14

क. 15981
दिनांक 12/12/14
प्र.स. 1 सा.प्र.वि. 2014

मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन,
मंत्रालय,
भोपाल (म.प्र.)

मुख्य सचिव कार्यालय
CS/Gen-Op/7036
Date 18-12-2014

Q (Signature)

15 DEC 2014
ACS, Finance
PS, GAD (HR)

विषय:- श्री राजेंद्र सिंह- पेंशन प्रकरणों के निराकरण बाबत।

माननीय आयोग के निर्देश दिनांक 31.10.14 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर आदेशानुसार लेख है कि- ऐसे कई और भी प्रकरण आयोग के सामने आये हैं जिनमें पेंशन व अन्य स्वत्व मिलने में अत्यधिक विलम्ब किया गया है इसलिए आप सभी विभागों व विभाग प्रमुखों को इस संबंध में निर्देश दें कि वे सेवा पुस्तिका की डुप्लीकेट पुस्तिका निर्माण संबंधी कार्यवाही एक निश्चित अवधि में पूर्ण किया करें जिससे सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी न हो। ऐसे जितने भी प्रकरण प्रदेश में लंबित हैं, उनमें एक निश्चित अवधि में निराकरण कराने के निर्देश मुख्य सचिव की ओर से जारी किये जाने से कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण होगी।

संलग्न आदेश की प्रति,

मा. आयोग के आदेशानुसार

17 DEC 2014
DS

18/12/14

उप सचिव
मानव अधिकार आयोग
भोपाल

12/12-2014
13/12-2014